

## उत्तराखण्ड की यूसीसी मसौदा रिपोर्ट

### प्रलिस के लिये :

[समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#), मौलिक अधिकार, [राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत](#)

### मेन्स के लिये:

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) मसौदा रिपोर्ट को [उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल](#) द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे अधिनियमन के लिये वधियक के रूप में 6 फरवरी 2024 को राज्य वधिनसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

- UCC मसौदा समिति का नेतृत्व [सर्वोच्च न्यायालय](#) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश [रंजना प्रकाश देसाई](#) ने किया।
- UCC [उत्तराखण्ड के सभी नविसयियों](#), चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, के लिये सामान्य कानूनों का एक प्रस्तावित सेट है।

### नोट:

- [भारतीय संवधान](#) का [अनुच्छेद 162](#) स्पष्ट करता है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक वसित है जिनके संबंध में राज्य के वधिनमंडल को कानून निर्माण की शक्ति है। [सातवीं अनुसूची](#) की [समवर्ती सूची की प्रवधि 5 के प्राधानों](#) को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता (UCC) को क्रियान्वति तथा कार्यान्वति करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकार क्षेत्र से बाहर के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  - [समवर्ती सूची की प्रवधि 5](#) "वविह और तलाक" शिशु तथा नाबालगि; दत्तक ग्रहण, वसीयत, नरिवसीयत एवं उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार व वभिजन से संबंधित है, सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्ष इस संवधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनके व्यक्तितगत कानून के अधीन थे।
- इसका अर्थ यह है कि [उत्तराखण्ड राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर UCC अधिनियमति कर सकती है।](#)

## उत्तराखण्ड की UCC मसौदा रिपोर्ट की मुख्य वशेषताएँ क्या हैं?

- UCC का लक्ष्य संवधान के [अनुच्छेद 44](#) द्वारा नरिदेशति, वविह, तलाक, दत्तक और वरिसत पर ध्यान केंद्रति करते हुए, हर धर्म के अलग-अलग व्यक्तितगत कानूनों को बदलना है।
  - संवधान [अनुच्छेद 44](#), [राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व \(DPSP\)](#) है। इसमें कहा गया है कि राज्य को संपूर्णभारत में [सभी नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता स्थापति करने का प्रयास](#) करना चाहिये।
  - यह मसौदा [व्यक्तितगत कानूनों का एक एकल सेट](#) होगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
- समिति द्वारा पेश किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में [बहुवविह](#), [इलाल](#), इददत (मुस्लिम वविह के वधितन के बाद महिलाओं द्वारा की जाने वाली प्रतीक्षा की अनविर्य अवधि), [तीन तलाक](#) एवं [बाल वविह](#) पर प्रतबंध, लड़कियों के लिये समान उम्र के साथ ही [सभी धर्मों में वविह तथा लवि-इन संबंधों का अनविर्य पंजीकरण](#) शामिल हैं।
- UCC के मसौदे का उद्देश्य वरिसत तथा वविह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करके [लैंगिक समानता](#) पर ध्यान केंद्रति करना है।
  - इस मसौदे में [मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तितगत कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा 25% हसिसेदारी के मुकाबले समान संपत्ति](#)

हस्तिसेदारी का वसितार करने की भी संभावना है।

○ पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु एक समान रखी गई है, महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिये 21 वर्ष है।

- अनुसूचित जनजाति (ST) को इस विधियक के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य में आदिवासी आबादी जो लगभग 3% है, उन्हें दिये गए विशेष दर्जे के कारण UCC के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।

## उत्तराखण्ड की UCC मसौदा रिपोर्ट के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- UCC मसौदा रिपोर्ट भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
  - कुछ आलोचकों का तर्क है कि UCC मसौदा रिपोर्ट भारत की विविधता तथा बहुलवाद के अनुरूप नहीं है एवं एक समान संहिता कार्यान्वयन करने का प्रावधान है जो विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।
- यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट से उत्तराखण्ड के ST के अधिकारों और हितों पर असर पड़ सकता है।
  - कुछ कार्यकर्ताओं का दावा है कि UCC मसौदा रिपोर्ट ST के मुद्दों और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान एवं स्वायत्तता को नष्ट कर सकती है।

## समान नागरिक संहिता क्या है?

- परिचय:
  - समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
    - हालाँकि संविधान निर्माताओं ने UCC को लागू करने का कार्य सरकार के वकिल पर छोड़ दिया था।
  - गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
  - मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (वर्ष 1985) मामला:
    - न्यायालय ने कहा कि "यह अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है" और इसके कार्यान्वयन का आह्वान किया।
    - इस तरह की मांग बाद के मामलों जैसे [?/?/?/?] [?/?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?], 1995 और [?/?/?] [?/?/?/?/?/?/?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?], 2003 में दोहराई गई थी।
- विधि आयोग का रुख:
  - वर्ष 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने "पारिवारिक विधि में सुधार" पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह माना गया कि "इस स्तर पर समान नागरिक संहिता का निर्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय"।
    - इसने रेखांकित किया कि धर्मनिरपेक्षता को देश में प्रचलित बहुलता के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिये। हालाँकि इसने सफ़ारिश की कि मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों/परसनल लॉ के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं तथा रूढ़िवादिता में संशोधन किया जाना चाहिये।
  - प्रारंभिक परामर्श पत्र जारी होने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने को स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 में, न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर UCC पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से राय मांगी।

और पढ़ें: [न्यायपूर्ण \(समान\) नागरिक संहिता](#)

## वधिकि दृष्टिकोण:

[समान अधिकार, कानून नहीं](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

भारतीय संविधान में प्रतष्टिठापति राज्य की नीतके नदिशक तत्त्वों के अंतरगत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. भारतीय नागरकों के लयि समान नागरकि (सविलि) संहति सुरक्षति करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटति करना
3. ग्रामीण कषेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहति करना
4. सभी श्रमकों के लयि उचति अवकाश और सांस्कृतकि अवसर सुरक्षति करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सदिधांत हैं, जो राज्य की नीतके नदिशक तत्त्वों में प्रतबिबिति होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून को लागू करने के मामले में कोई वधिान, जो कसिी कार्यपालक अथवा प्रशासनकि प्राधकिारी को अनरिदेशति एवं अनरिर्तृरति वविकाधकिार देता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति अनुच्छेदों में से कसिका उल्लंघन करता है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

**??????:**

प्रश्न. चर्चा कीजयि कविे कौन-से संभावति कारक हैं जो भारत को राज्य की नीतके नदिशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरकों के लयि समान सविलि संहति को अभनियिमति करने से रोकते हैं। (2015)